बेल्ट और रोड 2.0

लेखक- ध्रुव जयशंकर (फॉरेन पॉलिसी फेलो,ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन इंडिया सेंटर)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) से संबंधित है।

द हिन्दू

8 मई, 2019

"दूसरो बेल्ट एंड रोड फोरम के साथ एक विरोधाभास पहल की शुरुआत में ही स्पष्ट रूप से दिख रहा है।

इसके अनावरण के छह साल बाद, चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) ने खुद को एक और नए अवतार में प्रस्तुत किया है। अपने प्रारंभिक रूप में, यह सभी लोगों के लिए सब कुछ था अर्थात् चीन के अंतर्राष्ट्रीय जुड़ाव के लिए सभी को अपनी तरफ आकर्षित करना। लेकिन वास्तव में इसके कई बहुस्तरीय उद्देश्य थे।

पहला घरेलू अर्थशास्त्र से संबंधित है: चीन की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए, इसके औद्योगिक उत्पादन और इसके रोजगार के स्तर को ऊँचा बनाये रखने के लिए विदेशों में अधिशेष औद्योगिक क्षमता के निर्यात और नकदी भंडार को बेहतर बनाना। दूसरा घरेलू राजनीति से संबंधित है: चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ जुड़ने के लिए एक विदेशी पहल।

तीसरा सुरक्षा से संबंधित है: पश्चिमी प्रांतों और यूरेशियाई के आंतरिक इलाकों को स्थिर करना और चौथा रणनीति से संबंधित है: एशिया, अफ्रीका, यूरोप और हिंद तथा प्रशांत महासागरों में राजनीतिक उद्देश्यों के पूर्ती की पूर्ति चीन के नए-आर्थिक भंडार का

लाभ उठाना और अमेरिकी नेतृत्व को चुनौती देने के लिए नए मानकों और संस्थानों का निर्माण करना।

लेकिन बीजिंग बहुत जल्द और बहुत जल्दी स्थानांतरित हो सकता है। दूसरे बेल्ट एंड रोड फोरम (बीआरएफ) से यह निष्कर्ष निकलता है कि एक विरोधाभास पहल की शुरुआत में ही स्पष्ट रूप से दिख रहा है। चीनी परियोजनाओं की आर्थिक व्यवहार्यता अब काफी छानबीन के साथ देखी जा रही है। दुनिया भर की राजधानियों में, श्रीलंका के हंबनटोटा बंदरगाह को चेतावनी के रूप में

वर्णित किया जा रहा है।

चीनी ऋण के रूप में बीआरआई की स्थिरता को एक सवाल के रूप में देखा जा रहा है। इसके अतिरिक्त, यूरोपीय संघ, दक्षिण प्रशांत और कनाडा में भी सुरक्षा संबंधी चिंताएँ पैदा होने लगी हैं। व्यापार में चीन का एक राष्ट्र के रूप में हस्तक्षेप खुले तौर पर दिख रहा है। जिबूती में चीन के सैन्य अड्डे ने अपने बाहरी जुड़ाव के लिए एक अति सैन्य तत्व का निर्माण किया है।

फिर भी, इन स्पष्ट कमियों के बावजूद, BRI का आकर्षण मजबूत बना हुआ है। कई देश अभी भी चीन को धीमी गति से लोकतांत्रिक नौकरशाही और कठिन ऋण देने वाली संस्थाओं के लिए एक आकर्षक विकल्प के रूप में देखते हैं। इस खेल में राजनीतिक प्रेरणाएँ भी शामिल हैं: BRI पर एक छोटा समझौता, यूरोपीय संघ को एक मजबूत राजनीतिक संदेश भेजने के लिए इटली की यूरोसेप्टिक सरकार के लिए एक उपयोगी उपकरण है। इस वर्ष बेल्ट एंड रोड फोरम (BRF) के कमजोर प्रतीत होने के कारण बीजिंग भी अधिक लचीला हो गया है। इसके अलावा, 2017 के बाद से चीनी विदेशी वित्तीय प्रवाह भी धीमा हो गया है और इसका ध्यान बड़े पैमाने पर बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं से हटकर डिजिटल तकनीक जैसे क्षेत्रों में चला गया है।

इन विपरीत रुझानों को देखते हुए, BRI का भविष्य पहले से कहीं अधिक अनिश्चित लग रहा है। भारत द्वारा संप्रभुता (चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में) और अस्थिरता (विशेष रूप से हिंद महासागर में) के आधार पर दूसरी बार बीआरएफ का बहिष्कार करना यह सिद्ध करता है कि भारत, चीन के अंतर्राष्ट्रीय जुड़ाव पर पैनी नजर रखे हुए है।

GS World टीम...

वन बेल्ट, वन रोड

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में चीन के विभिन्न मार्गों से विश्व को जोड़ने वाले महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट 'बेल्ट एंड रोड फोरम' की दूसरी बैठक बीजिंग में संपन्न हुई।
- भारत और अमेरिका इस बैठक में शामिल नहीं हुए थे। हालांकि, इन दोनों देशों के अलावा, खरबों डॉलर के चीनी प्रोजेक्ट से संबंधित तीन दिवसीय सम्मेलन में करीब 37 देशों ने शिरकत की।
- चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट को वर्ष 2013 में शुरू किया था। इसका मकसद राजमार्गों, रेलवे लाइनों, बंदरगाहों और समुद्री रास्तों के जरिए एशिया, अफ्रीका और यूरोप को जोड़ना है।
- इस परियोजना के लिए चीन ने अरबों डॉलर अपने 60 साझीदार देशों पर खर्च किए हैं। श्रीलंका, मालदीव और पाकिस्तान जैसे उसके साझीदार देश उसकी परियोजना के तहत उसके कर्ज में डूब चुके हैं।

परिचय

- रेशम सड़क आर्थिक पट्टी तथा 21वीं सदी की सामुद्रिक रेशम सड़क की दो परियोजनाओं को मिलाने के लिये सितंबर, 2013 में 'वन बेल्ट, वन रोड' कार्यक्रम का प्रस्ताव दिया गया था।
- प्रस्तावित 'वन बेल्ट, वन रोड' 1400 अरब डॉलर की परियोजना है। ओबीओआर को 35 वर्ष में पूरा किये जाने का लक्ष्य है, जब 2049 में चीनी गणराज्य की 100वीं वर्षगाँठ मनाई जाएगी।
- विश्व के 55 प्रतिशत सकल राष्ट्रीय उत्पाद (जीएनपी), 70 प्रतिशत जनसंख्या तथा 75 प्रतिशत ज्ञात ऊर्जा भंडारों को समेटने की क्षमता वाली यह योजना वास्तव में चीन द्वारा भूमि एवं समुद्री परिवहन मार्ग बनाने के लिये है, जो चीन के उत्पादन केंद्रों को दुनिया भर के बाजारों एवं प्राकृतिक संसाधन केंद्रों से जोड़ेंगे।
- यहाँ 'बेल्ट' से तात्पर्य सिल्क रोड आर्थिक बेल्ट से है, जो तीन स्थल मार्गों से मिलकर बनी है- (i) चीन, मध्य एशिया और यूरोप को जोड़ने वाला मार्ग। (ii) चीन को मध्य व पश्चिम एशिया के माध्यम से फारस की खाड़ी और भूमध्यसागर से जोड़ने वाला मार्ग। (iii) चीन को दक्षिण-पूर्व एशिया, दक्षिण एशिया और हिन्द महासागर से जोड़ने वाला मार्ग।
- 'रोड' से तात्पर्य 21वीं सदी की समुद्री सिल्क रोड से है, जिसका निर्माण दक्षिण चीन सागर व हिन्द महासागर के माध्यम से चीन के तट से यूरोप में व्यापार करने तथा दक्षिण चीन सागर के माध्यम से चीन के तट से दक्षिण प्रशांत तक व्यापार करने के लिये किया गया है।

इन गलियारों से जाल बिछाएगा चीन

1. चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा
2. न्यू यूरेशियन लैंड ब्रिज
3. चीन-मध्य एशिया-पश्चिम एशिया आर्थिक गलियारा
4. चीन-मंगोलिया-रूस आर्थिक गलियारा
5. बांग्लादेश-चीन-भारत-म्यांमार आर्थिक गलियारा
6. इंडोचाइना-प्रायद्वीप आर्थिक गलियारा

चीन के लिये महत्त्वपूर्ण क्यों?

- विशेषज्ञों का मानना है कि 'वन बेल्ट, वन रोड' पहल चीन की आर्थिक कूटनीति का खाका है।
- विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि चीन स्वयं को अकेला महसूस करता है क्योंकि वह जी-7 में शामिल नहीं है और केवल ब्रिक्स देशों तक ही सीमित है।
- उनका मानना है कि अपने आर्थिक विस्तार को जारी रखने के लिये चीन को एक नीति की आवश्यकता थी और 'वन बेल्ट, वन रोड' पहल ने उसकी इस मंशा को बखूबी पूरा किया है।

भारत के लिए लाभ

- प्रतिस्पर्धी नेटवर्क स्थापित करने के लिये आज भारत में संसाधनों की कमी है। इसलिये वह OBOR के उन घटकों में भाग लेने के लिये उपयुक्त हो सकता है, जो प्रमुख बाजारों और संसाधनों की आपूर्ति के लिए भारतीय कनेक्टिविटी में सुधार ला सकते हैं।
- इसमें 60 देशों के साथ-साथ एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (एआईआईबी), ब्रिक्स के नव विकास बैंक, सिल्क रोड फंड, सीआईसी के समर्थन वाले कोष और संभवत: एससीओ विकास बैंक समेत कई अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान जुड़ रहे हैं और साथ ही इसे ऑस्ट्रेलिया का भी समर्थन हासिल है।
- यदि भारत को 2050 तक विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था या दूसरी सबसे बड़ी इकॉनमी बनना है, तो एशियन मार्केट को बिना एकीकृत किये यह संभव नहीं हो सकता है। इसलिए इस परियोजना में शामिल होकर भारत को एशियाई बाजारों के एकीकरण में हिस्सेदार बनना चाहिये और उसका लाभ भी उठाना चाहिये।

भारत पर प्रभाव

- भारत की सबसे बड़ी चिंता यह है कि यदि चीन का वन बेल्ट, वन रोड का सपना साकार हो गया, तो चीन निर्विवाद रूप से एशिया की सबसे बड़ी शक्ति के तौर पर उभरेगा, जिससे भारत की महत्त्वाकांक्षाओं को धक्का लग सकता है।
- पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से गुजरने वाला चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर (सीपीईसी) भी ओबीओआर का ही हिस्सा है।
- भारत, चीन-पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर के खिलाफ लगातार विरोध दर्ज करा रहा है। भारत की नजर में यह कॉरिडोर उसकी संप्रभुता को चुनौती देने वाला है।
- ओबीओआर के माध्यम से चीन अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं को नई दिशा देना चाहता है जो इसने दक्षिण एशिया में काम करना भी शुरू कर दिया है, जिसके लिए भारत पर इसका सीधा तथा प्रतिकूल प्रभाव होगा। चीन की इस पहल में भू-राजनीतिक उद्देश्य निहित हैं।

सिल्क रूट क्या है ?

- सिल्क रूट को प्राचीन चीनी सभ्यता के व्यापारिक मार्ग के रूप में जाना जाता है। 200 साल ईसा पूर्व से दूसरी शताब्दी के बीच हन राजवंश के शासन काल में रेशम का व्यापार बढ़ा। 5वीं से 8वीं सदी तक चीनी, अरबी, तुर्की, भारतीय, पारसी, सोमालियाई, रोमन, सीरिया और अरमेनियाई आदि व्यापारियों ने इस सिल्क रूट का काफी इस्तेमाल किया।
- ज्ञातव्य है कि इस मार्ग पर केवल रेशम का व्यापार नहीं होता था, बल्कि इससे जुड़े सभी लोग अपने-अपने उत्पादों: जैसे-घोड़ों इत्यादि का व्यापार भी करते थे।
- लद्दाख के एक बड़े इलाके पर चीन का कब्जा है, उसके पश्चिम में पाकिस्तान ने अपने कब्जे का एक बड़ा हिस्सा 1962 की भारत-चीन लड़ाई के बाद चीन को सुपुर्द कर दिया है। कराकोरम हाइवे कश्मीर में चीन का पहला trans-border infrastructure project है, जो साठ के दशक का है।
- तब से ही पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में चीन का दखल बढ़ता गया है। चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के साथ जुड़ने से कश्मीर विवाद में चीन की भूमिका और बढ़ गई है।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:-

1. वन बेल्ट, वन रोड परियोजना 2014 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा शुरू की गई थी।
2. चीन द्वारा जिबूती में सैन्य अड्डे का निर्माण किया गया है।
3. बेल्ट एण्ड रोड फोरम सम्मेलन (BRF) की दूसरी बैठक में विभिन्न देशों सहित भारत ने भी भाग लिया है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) 1 और 2
(b) केवल 2
(c) 2 और 3
(d) 1, 2 और 3

1. Consider the following statements-

1. One Belt One Road project was started by the president of China Xi Jinping in 2014.
2. China built military airport in Djibouti.
3. India also participated in the second meeting of Belt and Road Forum (BRF).

Which of the above statements is/are correct?

(a) 1 and 2
(b) Only 2
(c) 2 and 3
(d) 1, 2 and 3

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्रश्न:- चीन की महत्त्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एण्ड रोड इनिशिएटिव (BRI) के पीछे आर्थिक-सामरिक उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। क्या भारत सरकार द्वारा BRI का बहिष्कार एक उचित कदम है? टिप्पणी कीजिए। **(250 शब्द)**

Q. Explain the economic and strategic objectives of Belt and Road Initiative (BRI) a ambitious project of China. Is the boycott of BRI by India a good step? Comment. (250 Words)

GS World
Committed To Excellence

नोट : 7 मई को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(b) होगा।